stop wastage of government money and settle this immediately in view of the judgments given by the High Courts ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI : The Supreme Court has already given an interim judgment. A number of employees went to various courts. The Supreme Court has given an interim judgment on 3-5-1982 which asked the Railway administration to pay the petitioner the last-drawn salary. This, we are obeying, and the rest of it also, whatever may be the judgment, we will obey.

विश्व विद्यालयों में छात्र असन्तोष

* 271. †**श्री मनीराम बागड़ी** :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1983 के 'नवभारत टाइम्स' में 'विश्वविद्यालयों में छात्र असन्तोष की गहराती समस्याएं' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बढ़ते हुए असन्तोष, अव्यवस्था और अन्य गहन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P.K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of the 120 Universities in the country at present only 7 are functioning under Central Acts. The University Grants Commission has appointed a Committee to look into the functioning of these 7 Universities. This Committee will among others examine the reasons for periodic disturbances in the Central Universities and recommend remedial measures. The work of this Committee is now in the final stages.

As far as the remaining 113 State Universities are concerned the Central Government has been suggesting to all State Governments that they should set up appropriate machinery to consider the problems of students, teachers and non-teaching employees and take timely action to solve them so that the functioning of academic institutions is not disrupted.

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप रात-दिन अखबारों में पढ़ते हो, शिक्षा जो है वह देश का निर्माण और देश के वक्त के चलन का नाम है । आज विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की दशा क्या है—इस को आप समझ लें । इस के लिए इनका जो जवाब आया है वह न के बराबर है···**(व्यवधान)**···जब तक ये चुप नहीं रहेंगे, मैं बोलूंगा नहीं ।···**(व्यवधान)**···

शिक्षा के अन्दर बुनियादी दोष हैं—बंधा दाखला, महंगी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम, पढ़ने के बाद बेकारी, उपकुलपति के पद पर गुलाम-जहनियत के नौकरशाहों की नियुक्ति ।···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : इन को बता कर ही सवाल पूछूंगा । इन का जवाब कुछ भी नहीं है । बंधा दाखला—इतने लड़के-लड़कियां दाखिल होंगे, अंग्रेजी माध्यम···

अध्यक्ष महोदय : आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसलिये कि रिपीट करने के बाद भी इन को समझ में नहीं आता है । मंत्री जी को अच्छी हिन्दी आती है, लेकिन इन्होंने जवाब अंग्रेजी में दिया, फिर भी मैंने ऐतराज नहीं किया, अगर शीला कौल होती तो ऐतराज करता ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कान में आला लगा रखा है ।

श्री मनोराम बागड़ी : 7 विश्वविद्यालय हैं, जिनके बारे में खुलकर सवाल करता हूं--इन विश्वविद्यालयों में कितने लड़के-लड़कियों के दाखले का प्रबन्ध है, कितने लड़के-लड़कियों ने दाखले के लिए एप्लाई किया है और उनमें से कितनों को दाखला मिलेगा ? अंग्रेजी माध्यम को हटाने और शिक्षा को सस्ता करने के क्या उपाय कर रहे हैं ? जुहनी-गुलाम नौकरशाह, जो आई० पी० एस० और आई० ए० एस० हैं, उनको कुलपति के रूप में लाते हैं, उनके बजाय विश्वविद्यालयों में से हो जो शिक्षा के शास्त्री हैं, उन में से ही उपकुलपति लगाने का रास्ता सरकार कैसे अपना रही है ?

SHRI P.K. THUNGON : As regards abolition of English/medium I would like to say that there is no such proposal to abolish English medium in our Universities.

As regards various reforms about which the hon. Member has spoken, we have already taken certain measures to restructure the courses and in the plus 2 system vocational ducation is also included.

Moreover in the main text of my reply I have said that the UGC has appointed a committee to go into the details of these problems which the hon. Member has pointed out and that committee's work is in the final stages. As and when we receive the report from the committee, we will certainly look into those recommendations.

श्री बी० डी० सिंह : मूल सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री मनोराम बागड़ी : मैंने पूछा था कि कितने विद्यार्थियों ने दाखले के लिये एप्लाई किया है और कितनी दाखले की कैपेसिटी है ?

SHRI P. K. THUNGON : As regards all the seven Universities I do not have the figures here.

As regards Delhi University I will be able to tell the hon. Member through you that we have an intake capacity of 37,000 students in undergraduates programmes.

श्री मनोराम बागड़ी : आप के यहां एप्लाई कितनों ने किया है ?

SHRI P. K. THUNGON : Here so many students keep on applying not only to a particular college or University but to many other places also simultaneously they apply. So it is very difficult to assess what is the exact number of students who have applied and where.

श्री मनोराम बागड़ी : मैंने उपकुलपतियों के बारे में भी कहा था । केन्द्र के पास सात विश्वविद्यालय हैं । सात विश्वविद्यालयों में कितने उपकुलपति ऐसे हैं जो शिक्षा शास्त्रियों में से लिये गये हैं और कितने ऐसे हैं जो बाहर से, आई० ए० एस०, नौकरशाह और जहनी-गुलाम, आप ने, उपकुलपति बनाये हैं ? जैसे मिसाल के तौर पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने नौकरशाही-जहनियत की वजह से इसी सदन के एक सदस्य का अपमान किया था, हालांकि उस के बारे में दिये गये प्रिवलेज का अभी तक कुछ नहीं हुआ है । ऐसे आदमी को तो अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिये था··· **(व्यवधान)**···सात उपकुलपतियों में से कितने शिक्षा शास्त्रियों में से चुने गये हैं ? और कितने ऐसे आई० पी० एस० और आई० ए० एस० गुलाम-जहनियत नौकरशाहों को उपकुलपति रखा हुआ है ।

श्री पी० के० थुंगन : हमारे यहां 7 यूनिवर्सिटियों में से 2 उपकुलपति इस प्रकार के हैं, जो सर्विसेज में से लिये गये हैं और बाकी जो हैं, वे शिक्षा शास्त्री हैं ।

श्री मनोराम बागड़ी : कौन-कौन से ?

SHRI P. K. THUNGON : I don't mind telling the names of the universities—one is the A.M.U. (Aligarh Muslim University) and the other is the J.N.U.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह जो प्रश्न है, इस का जवाब केवल खानापूरी के लिए दे दिया है । प्रश्न यह पूछा गया था कि देश के

विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए असन्तोष, अव्यवस्था और अन्य गहन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ? अब इसका जवाब मंत्री जी ने यह दिया है कि "देश में 120 विश्वविद्यालयों में से इस समय केवल 7 विश्वविद्यालय केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।" इस तरह से बाकी जो 113 विश्वविद्यालय हैं, आप ने राज्य सरकारों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है और कहा है कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है और उनके बारे में आप कुछ मालूम नहीं है। जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन को ही आप ठीक नहीं करवा रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कचकच होती है। इसी तरह की स्थिति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की है। एक हफ्ते से छात्र हड़ताल कर रहे हैं और उपकुलपति का घेराव किया गया है और वह भी आप संभल नहीं पा रहा है। इसी तरह की स्थिति काशी विद्यापीठ, मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की है। यह मामला कैसे हल होगा। मैं इस संदर्भ में आप से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस को रोकने के लिए क्या कर रही है। ये जो आन्दोलन हो रहे हैं और छात्रों में गड़बड़ है और इसके साथ-साथ छोटे-छोटे कर्मचारियों और प्रोफेसरों में यह गड़बड़ चल रही है, ऐसा लगता है कि सरकार इनको खुद बढ़ावा दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब समस्याओं को हल करने के लिए आप तुरन्त क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर का जो कोर्स था, उसके बारे में शैड्यूल्ड कास्ट्स ओर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो हड़ताल पर थे, उनके सम्बन्ध में आप ने क्या किया है और कितनों का वहां पर दाखिला हुआ है ?

SHRI P.K. THUNGON : I have already stated about what we are doing regarding the university problems. If the hon. Member has read the reply properly, he would find that regarding the universities which are run by the States we have been writing to them and advising them to form such Committees to look after the interests of the Students, teachers and the Karamcharis.

As regards the seven universities, I have already very clearly stated that the U.G.C. has appointed a Committee to go into the details of these problems. The problems which the hon. Member has explained would also be gone into by that Committee. I have also stated that it is in the very advanced stage and we expect that the report would be submitted very soon by that Committee.

Regarding the problems about the J.N.U. which the hon. Member has stated, namely, the unrest caused due to certain problems in regard to computer science system, I would like to state that that problem arose from a point when one teacher had abused a scheduled caste student. Thereafter, the students wanted the teacher to be suspended. After that the students also gheraoed the officers and, later on, the Vice-Chancellor agreed to form a Committee to look into that part of the working of the computer science system. It is still at that stage.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर एक तो इन्होंने राज्य सरकारों का मामला बताया है। वह भी इन्होंने गड़बड़ बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों का ये कैसे करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कम्प्यूटर के बारे में ये क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। कमेटी बना दी है।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : मैंने इसके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया है। इस पर हाउस हाफ एन आवर डिस्कशन भी चाहता है।

(व्यवधान)

SHRI HARIKESH BAHADUR : My point is that there is unrest in almost all the Central Universities, apart from the State Universities, like the Jawaharlal Nehru University, Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University. And whenever we have tabled a question, this has been the reply from the Hon. Minister that an Inquiry Committee had been instituted or an Expert Committee has been instituted and it would give its report very soon. But what is the time limit ? Why is the Government not going to fix the time limit for such a Committee to submit its report ? How long Government can say that there is a committee and that it will submit a report ? When this Government will go out of power, will it at that time submit its report ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Will it be that soon ?

(nterruptions)

SHRI RAM PYARE PANIKA : Sir, Harikesh Bahadur is not serious at all.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Therefore, I would like to know whether the Hon. Minister is going to fix a time limit to that committee so that it can submit its report in time ? And at the same time what is the Government going to do in order to solve the problems of the Banaras Hindu University, and the Jawaharlal Nehru University where, strike is going on and the students, Karamcharis and all are agitating. So, I would like to ask the Hon. Minister what is he going to do in order to solve the problems of the Universities.

SHRI P. K. THUNGON : Sir, as regards the fixing of the time limit for the Committee the Hon. Member wiil be glad to know that the Committee is going to submit its report by the end of next month.

As regards solutions to be found for BHU or the Delhi University or the JNU, whichever Univresity the Hon. Member has stated, naturally in that Committee's Report certain suggestions will be contained. We will take action according to those suggestions.

श्री रशीद मसूद : मोहतरम, अभी मिनिस्टर साहब ने यू. जी. सी. की कमेटी के बारे में बताया है । इस बारे में मैं मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा को 50 से ज्यादा खत लिख चुका हूं और उनके जवाब भी मेरे पास आये हैं । ये यू. जी. सी. कमेटियां क्या करती हैं ? ये हैड आफ द डिपार्टमेंट के कमरे में जाकर के बैठ गई और वहां से चाय पी कर के चली आई । ये कोई काम नहीं कर रही हैं । मैं इसके बारे में भी लिख चुका हूं । इन कमेटियों के बारे में न कोई नोटिफिकेशन होता है और न कोई पब्लिसिटी होती है ताकि लोग अपनी ग्रिवांसिज उनके सामने जा कर के रख सकें । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस चीज को देखे ।

दूसरे 161 मेम्बरान ने मेमोरेण्डम दिया था जिसको कि दो साल हो गये । उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ । अभी मैं आपकी इजाजत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दो आर्डर्स के बारे में बताना चाहता हूं । एक आर्डर के मुताबिक उन्होंने एक साहिब की सर्विसिज टरमिनेट कर दी थी । उसके बाद 6 महीने बाद वे वापस आ जाते हैं । पता नहीं कैसे मेन्युवरिंग करते हैं, क्या करते हैं, वहां यूनिवर्सिटी में तो इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं ।

लेकिन फिर दूसरा आर्डर जाता है और उसमें कहा जाता है कि चूंकि आप वर्बली इजाजत लेकर गए थे । लिहाजा अपनी छुट्टी को कंसिडर किया जा रहा है और आप अनअथोराइज्डली बाहर नहीं थे और उनको छुट्टी दे दी जाती है । इस तरह का खेल हो रहा है । कैसे काम चलेगा ? यू. जी सी. की कमेटी आपने बिठाई है । क्या आप उस कमेटी के बारे में वाइड पब्लिसिटी देंगे ताकि तमाम लोग अपने—ग्रीवेसिस उसके सामने रख सकें ?

कम्प्यूटर साइंस के बारे में जो जिक्र अभी माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने किया है

उसका जवाब नहीं दिया गया है। पिछले साल में कम्प्यूटर साइंस के अन्दर एस. सी. एस. टी. के किसी लड़के का नाम लिया गया है जिस को दाखला नहीं मिला। इस में ही नहीं और भी कई कोर्सिस हैं जिनमें जगहें खाली रखी जाती हैं और जनरल से उनको फिल कर लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोशिश करेंगे कि खासतौर से टैक्नीकल डिमार्टमेंट्स में जो सीटें इनके लिए रिजर्व्ड हैं उनके अगेंस्ट इनको दाखिला मिले जोकि अब तक नहीं दिया गया है ? मैं इसका कैटेगोरिकल जवाब चाहता हूं।

श्री पी० के० थुंगन : पब्लिसिटी के बारे में जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर हम जरूर गौर करेंगे। एडमिशन के लिए भी जो सुझाव दिया है उस पर भी हम गौर करेंगे।

श्री रशीद मसूद : गौर का क्या मतलब है ? मैं आप से अपने सवाल के बारे में अलग से आपके चैम्बर में बात कर लूंगा। लेकिन इसका आप कैटेगौरिकल जवाब तो दिलवाएं कि रिजर्व्ड सीट्स जो इनकी हैं उनके अगेंस्ट इनको दाखिला दिया जाएगा।

श्री पी० के० थुंगन : रिजर्व्ड सीट्स के मुताबिक उनको जगहें दी जाती हैं। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत होगी तो वह भी करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या करेंगे इसका स्पेसेफिक उत्तर आना चाहिए। एस. सी. एस. टी. का मामला आता है तो ऐसे ही सब बात खत्म हो जाएगी ?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : The question relates to the unrest in the universities. I would like to ask a pointed question : the Assam agitation is going on for the last four years. Is it a face that the main centre of the AASU is the university campus at Gauhati, and that several times, the Police have detected many illegal papers, and also documents and explosives ? What steps is Government taking to look into this particular matter ?

MR. SPEAKER : This is a subject. Mr. Minister, have you got any reply to this ?

SHRI P. K. THUNGON : I agree with the hon. Member to the extent that in some cases, the University's facilities have been used by the students' union. For the rest of the details, I would not be able to explain things to him, because they are looked into by the State.

श्री राम विलास पासवान : मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बाकी सारों ने टेढ़ा पूछा है।

श्री राम विलास पासवान : सवाल सीधा था लेकिन जवाब टेढ़ा था।

क्या यह सही है कि जे० एन० यू० के प्रो० के० वी० सक्सेना के खिलाफ जातीयता बरतने का आरोप था और थाने में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया ? यदि किसी के ऊपर छुआछूत का मामला हो और थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसको फौरन ससपेंड किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रोफेसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया अब तक ?

क्या सरकार इस तरह का कानून बनाएगी कि जो प्रोफेसर या अध्यापक जातीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, धार्मिक आधार पर डिसक्रिमिनेशन करता है उसको फौरन सस्पेंड किया जा सकेगा ?

SHRI P. K. THUNGON The hon. Member has raised this question earlier also once on the floor of this House. I would like to explain to him that his demand that the teachers be suspended, cannot be acceded to, because of the fact that firstly, the University teachers are not governed by the rules of Government employees; and secondly, as far as the point regarding the case that has been registered in the police station is concerned, unless and until it is investigated and further rulings are available on that very case, it is not possible to take any action.

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी ने जो जवाब अब दिया है और पहले जो यहाँ जवाब दिया गया था, दोनों डिफर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चेयर में थे, श्रीमती शीला कौल ने कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा और उनको सस्पेंड कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कहा गया है।

फाइंडिंग जो होंगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महदोय : मैंने भी उस दिन कहा था, मेरी अपनी भी औबजर्वेशन थी अगर ऐसा किसी ने किया था तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं क्या वह सब हो गया है या नहीं ?

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : What is the opinion of the government on the allegation ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : The point is if that has been established or not.

SHRI P. K. THUNGON : So far as we are concerned, that has not yet been established. Whatever I told the hon. member is the same thing which my Minister had told earlier on the Floor of this House. (*Interruptions*).

MR SPEAKER : The question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी और निजी कालेजों/अस्पतालों से निकलने वाले डाक्टर

* 272. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कालेजों और निजी कालेजों/अस्पतालों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रति वर्ष अलग-अलग कितने (एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी) डाक्टर निकलते हैं;

(ख) उनमें से प्रति वर्ष कितने डाक्टरों को रोजगार मिलता है और कितने डाक्टर बेरोजगार रहते हैं; और

(ग) भारत से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने डाक्टर रोजगार के लिये बाहर गये हैं और उनके बाहर जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी कालेजों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्नातक होकर निकलने वाले डाक्टरों (एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी) की संख्या इस प्रकार है :

एलोपैथी	12,170	(1980-81)
होम्योपैथी	1,903	(1981)
आयुर्वेद	1,696	(1981)
यूनानी	196	(1981)

(ख) बहुत से स्नातक डाक्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। कई राज्य और केन्द्र की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में लग जाते हैं। बहुत से अपना कारोबार करने लगते हैं। इस प्रकार यह देखते हुए कि स्नातक होकर निकले डाक्टरों को रोजगार के इतने रास्ते खुले हैं, यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने डाक्टरों को रोजगार मिलता है अथवा कितने बेरोजगार रह जाते हैं।

(ग) जो डाक्टर अध्ययन/रोजगार के लिए विदेश चले गये हैं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

Bangladesh Move to Form Anti-Indian Bloc

*273. SHRI B. V. DESAI :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Bangladesh has initiated a move to group the smaller nations in the Indian sub-continent together to build up a bulwark against India;